



भारतीय शिक्षा का महत्व

शोधार्थिनी-स्वीटि कुमारी एवं प्रो० विभा चौहान

जे०एस० यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद (शिक्षा विभाग)

समीक्षा:—

प्रस्तुत अध्ययन की अपेक्षाओं की दृष्टि से शिक्षा के भारतीयकरण अथवा स्वदेशीकरण का तात्पर्य है भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन दर्शन और भारतीय की आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं को भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार बनाना, जिससे वह सचमुच 'भारतीय' नागरिकों का निर्माण कर सकें। यह सिद्धान्त केवल भारतीय शिक्षा पर ही लागू नहीं होता। विश्व के सभी शिक्षाविद् यह मानते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय संस्कृति के सन्धारण परीक्षण एवं सम्बद्ध का साधन होती है। उदाहरण के लिये यदि अमेरिकी शिक्षा प्रणाली अमेरिका के भावी नागरिकों को ब्रिटिश जीवन पाति के लिये तैयार करती है तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली इंग्लैण्ड के भावी नागरिक को अमेरिकी जीवन पाति के लिये तैयार करती है और रूसी शिक्षा प्रणाली रूस के भावी नागरिकों को उसकी जीवन पाति के लिये तैयार करती है। किन्तु भारतीय शिक्षा प्रणाली भारत के भावी नागरिकों को भारतीय

जीवन प्राप्ति के लिये तैयार नहीं करती क्योंकि इसके आधार के रूप में भारतीय जीवन-दर्शन एवं भारतीय जीवन-प्राप्ति जैसे किसी दर्शन तथा जीवन प्राप्ति का अस्तित्व नहीं है। भारतीय प्रणाली सदा से इस दुखद स्थिति में नहीं थी।

हम उपर्युक्त विचारों के पुष्टि हेतु पं. पदन मोहन मालवीय के शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं—

जो शिक्षा प्रणाली देश के अन्तमार्ग से सहज रूप से उत्पन्न होती है तथा अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों, समस्याओं, आवश्यकताओं, आदर्शों एवं आकांक्षाओं तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अनुरूप विकसित होती हैं, वही राष्ट्रीय शिक्षा है। ठीक इसी प्रकार की शिक्षा ब्रिटेन तथा अमेरिका में विकसित हुई है। विदेशी शिक्षा पाति, जो हम लोगों के देश में अंग्रेज शासकों द्वारा प्रचलित की गयी, राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कही जायेगी, क्योंकि इसका लक्ष्य तथा उद्देश्य समस्त राष्ट्र के उत्थान के निमित्त सुयोग्य, आदर्शवादी, उत्तरदायी और अनुशासनबद्ध नागरिकों का निर्माण करना नहीं, प्रत्युत अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये विशाल भारतीय जनसमूह के एक अंशमात्र को लिखने-पढ़ने भर की शिक्षा देकर अपने शासनसूत्र का आधार दृढ़ करना था। 2 फरवरी 1835 ई को वर्तमान अंग्रेजी शिक्षा के विधायक लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की नई नीति के प्रारम्भ के अवसर पर भारतीय और अरबी साहित्य को निरर्थक, निराधार, मूर्खतापूर्ण, असत्य और असंगत बताते हुए बड़े विस्तार के साथ कहा है कि "हम यह चाहते हैं कि भारतीय केवल रंग में ही भारतीय

रहें, किन्तु खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार आदि सभी बातों में वे पूर्णतः अंग्रेज बन जायें।”

जैसा कि पूर्व पंक्तियों में कहा जा चुका है, लार्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा को भारतीय जीवन-दर्शन एवं जीवन-पति से पृथक किया और उसे पाश्चात्य जीवन-दर्शन एवं जीवन-पति के प्रसार का साधन बनाया। मैकाले के इस इत्य से होने वाले परिणामों का उल्लेख किया जा चुका है।

भारत के दूरदर्शी राष्ट्र निर्माताओं को मैकाले द्वारा रचे गये षड़यन्त्र को समझने में देर नहीं लगी। यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन को भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया। दयानन्द, अरविन्द, टैगोर आदि महापुरुषों तथा उनके अनुयायियों ने भारतीय जीवन-दर्शन एवं जीवन-प्राप्ति पर आधारित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। ऐसी शिक्षा संस्थाओं में से गुरुकुल कांगड़ी, अरविन्द आश्रम तथा शान्ति निकेतन विश्व भारती के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये शिक्षा संस्थायें भारत के प्राचीन गुरुकुला में एवं विश्वविद्यालयों से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। इन शिक्षा संस्थाओं के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक ओर कम्पनी द्वारा आरोपित विदेशी शिक्षा प्रणाली अंग्रेज तथा अंग्रेजियत के भक्त “सेवक” तैयार कर रही थी वही दूसरी ओर इन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में मातृभूमि के लिये मर मिटने वाले स्वाभिमानी सेनानियों का निर्माण हो रहा था दुर्भाग्य से, स्वतन्त्र

भारत में इन महान राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं का भी आंग्लीकरण कर दिया गया जिसके कारण इनका भारतीय स्वरूप नष्ट हो गया है। यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलन के प्रति महात्मा गाँधी के योगदान का विस्तृत वर्णन किया जाना समीचिन न होगा, किन्तु यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि

गान्धी जी विदेशी शिक्षा प्रणाली के दुष्परिणामों से भली-भाँति परिचित थे और शिक्षा के भारतीयकरण के प्रबल समर्थक थे। महात्मा गान्धी के शब्दों में—

“मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद रखी थी उसने हमें गुलाम बना दिया है। मेरा यह कहना नहीं है कि उसका कोई ऐसा इरादा था, परन्तु फल यही निकाला है। क्या यह दुख की बात नहीं है कि हमें स्वराज्य की बात एक विदेशी भाषा में करनी पड़ती है। विदेशी माध्यम ने हमारे बच्चों को उनके अपने देश में ही विदेशी बना दिया है। वर्तमान शिक्षा-पाति की यह एक अत्यन्त दुखद विडम्बना है। विदेशी माध्यम से हमारी मातृभाषाओं की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध किया है। यदि मुझे एक निरकुंश शासक के अधिकार प्राप्त होते तो मैं अपने बालक-बालिकाओं को विदेशी माध्यम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पर रोक लगा देता और सभी अध्यापकों और प्राध्यापकों को निकाल बाहर करता जो इस परिवर्तन को तुरन्त स्थान न दे पाने में असमर्थ होते। मैं पाठ्यपुस्तकों की तैयारी के लिये प्रतीक्षा न करता परिवर्तन के पश्चात् वे तयार होती रहती। यह एक ऐसा दोष है जिसका जड़-मूल से इलाज आवश्यक है।”

महात्मा गांधी ने “यंग इण्डिया” में मार्च 1924 में प्रचलित भारतीय शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किये—

“जिस पाठ्यक्रम से और शिक्षा—सम्बन्धी जिन विचारों से वर्तमान शिक्षा का ढाँचा बना है, उनका आधार आक्सोड एडिनबरा आदि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम है। इसलिये वे मूलतः विदेशी हैं..... वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी—बुराई, जो स्वयं अधिक गहरे दोषों का प्रमाण है, यह है कि उसने हमारे जीवन की अविच्छिन्नाता को भंग कर दिया.....यह सम्पूर्ण शिक्षा—प्राप्ति ही बुरी है, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय जीवन और विकास की जड़ों को ही नष्ट कर रही है। अतएव यह प्रणाली उठा ही दी जानी चाहिये और इस बात की फौरन जाँच होनी चाहिये कि भारतीय विश्वविद्यालयों के बनने तथा शिक्षा के सम्बन्ध में लार्ड मैकाले की घातक सम्मति लिखी जाने से पहले भारतीय विश्वविद्यालयों के बनने तथा शिक्षा के सम्बन्ध में लार्ड मैकाले की घातक सम्मति लिखी जाने से पहले भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या था”?

यंग इण्डिया 1921 में गान्धी ने अपने विचार पुनः इन शब्दों में व्यक्त किये—

“यह शिक्षा प्रणाली एक खालिस बुराई है। मैं इस शिक्षा—प्रणाली को नष्ट करने के लिये अपनी शक्ति लगा रहा हूँ। मैं यह नहीं कहता कि हमें अभी तक इस प्रणाली से कोई भी लाभ नहीं मिला है। लेकिन हमें अभी तक जो लाभ मिले हैं वे उस प्रणाली के कारण नहीं, बल्कि उसके बावजूद मिले हैं। मेरा कहना यह है कि शिक्षा का मूल्यांकन

आप उसकी सच्ची ममता और उसकी गरिमा के आधार पर करें। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें नपुंसक बना दिया है और हमारी प्रज्ञा कुण्ठित कर दी है। जिस तरह यह शिक्षा दी जाती है, उसके कारण हम कमजोर और कायर बन गये हैं। हम स्वतन्त्रता की धूप तो सेकना चाहते हैं, परन्तु दास बनाने वाली यह पद्धति हमारे राष्ट्र को नपुंसक बनाये डाल रही है..... यह एक शैतानी प्रणाली है।” अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्ति ने भारतीय जीवन की उपेक्षा की। इस सम्बन्ध में गान्धी जी के शब्द इस प्रकार हैं—

“मैकाले ने हमारे साहित्य का तिरस्कार किया, हमें अन्धविश्वासी माना। जिन लोगों ने हमारी शिक्षा की योजना बनाई, उनमें से अधिकांश को हमारे धर्म के बारे में गहरा अज्ञान था। कितनों ने ही उसे अधर्म समझा। उन्होंने हमारे धर्म ग्रन्थों को अन्धविश्वासों का समुच्चय माना। उन्हें हमारी सभ्यता दोषपूर्ण मालूम हुई। यह समझा गया कि हमारा राष्ट्र अवनत है, और इसलिये हमारी प्रणालियों में बहुत दोष होने चाहिये। इससे शुद्ध भावना होते हुए भी उन्होंने प्रणाली गलत बनाई। चूँकि रचना नई करनी थी इसलिये प्रयोजकों ने तत्कालीन परिस्थितियों का ही ध्यान रखा। उन्होंने सारी योजना इस ख्याल को आगे रखकर बनाई कि उन्हें अपनी सहायता के लिये वकीलों, डाक्टरों और क्लर्कों की आवश्यकता होगी और हम सबको इस ज्ञान की जरूरत होगी। इसलिये उन्होंने हमारे जीवन की उपेक्षा की और उन्होंने गाड़ी के पीछे घोड़ा जोत दिया।”

1947 के पश्चात् भारत सरकार ने तीन राष्ट्रीय शिक्षा आयोगों की नियुक्ति की है।
(1) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49). (2) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)
और (3) शिक्षा आयोग (1964-66)।

सन्तोष का विषय है कि इन तीनों राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने-अपने ढंग से शिक्षा के भारतीय अथवा स्वदेशीकरण का समर्थन किया है और यह अभिस्ताव किया है कि भारतीय शिक्षा का आधार भारतीयता, भारतीय जीवन-दर्शन एवं भारतीयों की आकांक्षाओं को ही होना चाहिये। उदाहरण के लिये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है—

We must have a conception of the social order for which we ure education or youth We know what Hitler did in six years with the German Youth The Russians are clear in their minds about the kind of society for which they are education and the qualities required in their citizens. They tried to remake man in a new image, our educational system must mind its guiding principle in the aims of the social order for which it prepares, in the nature of the civilization it hopes to build, unless we know, whether we are tending. We can not decide what we should do and how we should do it. Socieites like men need a clear propose to keep them stable in world of buildering change.

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने समाज के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आयोग के ही शब्दों में—

Everyone should know something of the society in which he lives, the great force that mould contemporary civilization, history, economics, Politics, social psychology, anthropology belong to the group of socialsciences, whatever may be our specialised field, a general understanding of our social environment and of human institutions is essential.

राधाकृष्णन आयोग विद्यमान शिक्षा प्रणाली के चरित्र को अभारतीय मानता है जिसमें भारतीय संरक्षति की घोर उपेक्षा हुई है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करते हुए राधाकृष्णन् आयोग कहता है—

The Un-Indian character of Education is one of the serious complaints against the system of education which has prevailed in this country for ever a century is that it neglected India's past, that it did not provide the Indian students with knowledge of their own culture. It has produced in some cases the feeling that we are without roots in others what is worse, that our roots bind us to a world every different from that which surrounds us.

राधाकृष्णन आयोग का स्पष्ट मत है कि भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीयों को उनकी प्राचीन संस्कृति की महानता से परिचित कराना होना चाहिए। आयोग केशब्दों में—

The Chief source of spiritual nourishment for any pupil must be its our past prepetually rediscovered and renewed. A society without a knowledge of the past which has made it would be lacking in depth of dignity.

और भी—

Even in the darkest days of degradation, the light of India's culture never failed, it may have flickered but it was never extinguished. There were loving hands which cherished and tended it today it is burning with a renewed glow. If it is to become a consuming flame, we must become aware of its past greatness and its contemporary value.

“माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना है कि भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण प्रायः पुस्तकों तथा प्रतिवेदनों में वखणत सामान्य उद्देश्यों के रूप में किया जाता रहा है, किन्तु उनकानिर्धारण राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आदर्शों के सन्दर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों के रूप में किया जा सकता है।” माध्यमिक शिक्षा आयोग के शब्दों में—

The aims of education have been formulated in general terms in numerous books on education and in the Report of Committees and commission and

therefore, so far as such general aims are concerned, it is not possible to add anything significant to what has been repeatedly expressed. But there is undoubtedly room for formulating these aims in more specific terms and with special reference of the needs and the ideals of our country in its actual situation. As political, social and economic conditions change and new problems arise. It becomes necessary to re-examine carefully and re-state clearly the objectives which education at each definite stage, should keep in view. Moreover this statement must take into account not only the facts of the existing situation but also the direction of its development and the nature and type of the social order that we envisage for the future to which education has to be geared.

शिक्षा आयोग (1964–66) ने भी यह स्वीकार किया है कि “शिक्षा की वर्तमान प्रणाली का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है उसकी विषय वस्तु तथा प्रयोजनों एवं राष्ट्रीय विकास की समस्याओं तथा उसके बीच बड़ी चौड़ी खाई है। उदाहरणार्थ इस शिक्षा प्रणाली में उस कृषि की सर्वाधिक महत्ता प्रतिबिम्बित नहीं होती जिसकी उपेक्षा सभी अवस्थाओं पर की जाती है और जिसकी ओर देश की चोटी की प्रतिभाओं का समुचित अंश आकृष्ट नहीं होता।”

शिक्षा-आयोग ने भी स्वीकार किया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीयचेतना को बढ़ावा देने की कोई परम्परा नहीं है। अतः शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है—

“यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी स्कूल प्रणाली में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित करने की कोई ठोस परम्परा नहीं है। ब्रिटिश राज्य में स्कूलों से यह आशा की जाती थी कि वे मातृभूमि के प्रति प्रेम की आवना उत्पन्ना करने के बजाय ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ायें। इसका परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्रीय चेतना विकसित करने का काम शिक्षा प्रणाली से बाहर विशेषतः 1900–1947 के बीच राष्ट्रीय आन्दोलन; स्वतन्त्रता संघर्ष द्वारा किया गया। उसकी नीव में फिर से जागा यह विश्वास या कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और परम्पराएँ महत्वपूर्ण हैं तथा भारत की प्राचीन सफलताओं पर हमें गर्व करना चाहिए।”

राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा-आयोग ने सुझाव दिया “राष्ट्रीय चेतना को गहरा बनाने के लिये विशेष रूप से दो कार्यक्रम अपनाये जा सकते हैं—1. हमारी सांस्कृतिक विरासत का फिर सेमूल्यांकन करना तथा उसे समझना तथा 2. जिस भविष्य की हम कामना करते हैं, उसके प्रति दृढ़ प्रेरणा पूर्ण निष्ठा उत्पन्ना करना। प्रथम की पूखत भाषाओं तथा साहित्यों, दर्शन, धर्मों तथा भारतीय इतिहास के सुनियोजित अध्यापन तथा विद्यालयों को वास्तुकला, मूखतकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य तथा नाट्य

से परिचित कराके की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों सम्बन्धी अध्ययन को पाठ्यचर्या में शामिल कर जहाँ सम्भव हो वहाँ शिक्षकों का आदान-प्रदान कर, देश के विभिन्नभागों में स्थित शिक्षा-संस्थाओं में भाईचारे के सम्बन्धों को बढ़ावा देकर तथा प्रादेशिक या भाषायी बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर छुट्टी शिविरों तथा ग्रीष्म स्कूलों का आयोजन कर, इन भागों से सम्बन्धित ज्ञान को और अधिक बढ़ाने एवं समझने और सराहने की वृत्ति को प्रोत्साहित करना वाछनीय होगा। यह और भी आवश्यक होगा कि कुछ ऐसी अखिल भारतीय संस्थायें स्थापित की जायें और बनायी रखी जायें जो कि देश के विभिन्नभागों के विद्यालयों को अपने यहाँ प्रवेश दें। भविष्य में निष्ठा के लिये नागरिकता सम्बन्धी पाठ्यक्रम में विद्यालयों को संविधान के सिद्धान्तों, उसकी प्रस्तावना मे उल्लिखित महान् मूल्यों, जिस लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, उसके स्वरूप को समझाने तथा राष्ट्रीय विकास की पंचवर्षीय योजनाओं को भली प्रकार समझाने का प्रयत्न करना होगा। शिक्षा के उच्च स्तर पर विद्यालयों को आधुनिक आन्दोलनों तथा प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करना सीखना चाहिए ताकि वे यह सीख सकें कि उनमें से किन्हें अपनी संस्कृति में आत्मसात किया जा सकता है या किया जाना चाहिये। किन्तु हमें इस बात की सावधानी बरतनी चाहिये कि सारे ही आधुनिक मूल्य "पाश्चात्य" मूल्य नहीं हैं।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में यह स्वीकार किया गया कि "प्रत्येक देश अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक अस्मिता और अभिव्यक्ति देने और पनपने के लिये और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिये अपनी विशिष्ट प्रणाली विकसित करता है। लेकिन देश के इतिहास में कभी-कभी ऐसा समय आता है जब मुद्दों से चले आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा में देने की नितान्त जरूरत हो जाती है। आज वही समय है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने यह भी लिखा है—"राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिये एक राष्ट्रीय शिक्षाक्रम के ढाँचे पर आधारित होगी जिसमें एक "सामान्य केन्द्रिक" का मन कोरबद्ध होगा और अन्य हिस्सों की बाबत लचीलापन रहेगा। जिन्हें स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा।

"सामान्य केन्द्रिक" में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, सवैधानिक जिम्मेदारियाँ तथा राष्ट्रीय अस्मिता से सम्बन्धित अनिवार्य तत्व शामिल होंगे। ये मुद्दे किसी एक विषय का हिस्सा न होकर लगभग सभी विषयों में पिरोये जायेंगे। इनके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों को हर इंसान की सोच और जिन्दगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जायेगी। इन राष्ट्रीय मूल्यों में ये बातें शामिल हैं—हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, स्त्री-पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समानता, सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक तरीके के अमल की जरूरत.....भारत

के विभिन्न देशों में शान्ति और आपसी भाई चारे के लिये सदा प्रयास किया है, और "वसुधैव कुटुम्बकम्" के आदर्शों को संजोया है। इस परम्परा के अनुसार शिक्षा—व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना बढ़े। शिक्षा के इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती।"

(ग) प्रस्तुत अध्ययन और शिक्षा का भारतीयकरण :-

उपर्युक्त विवेचन से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

(1) (1835) के पश्चात् योजनाबद्ध रूप से भारतीय संरक्षति तथा भारतीय शिक्षा के मध्य पृथक्करण किया गया जिसके दुष्परिणामों को भारतवासी आज तक भोग रहे हैं और (2) सभी भारतीय राष्ट्र निर्माता तथा राष्ट्रीय शिक्षा—आयोग यह स्वीकार करते हैं कि यदि भारतीय शिक्षा को भारत राष्ट्र के नव निर्माण का एक प्रभावी साधन बनाना है तो शिक्षा का भारतीयकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा के भारतीयकरण का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि हम ऋग्वेद से लेकर रामचरित मानस तक और तत्पश्चात् आज तक उपलब्ध अपने समस्त सांस्कृतिक एवं साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करें और उनमें से शिक्षा के विभिन्न अंगों—उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि से सम्बन्धित तत्वों एवं सिद्धांतों का चयन करें। तत्पश्चात् हम भारतीयों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की दृ

ष्टि से इस प्रकार चयनित विचारों का मूल्यांकन करें और युगानुरूप उपयोगी शैक्षिक विचारों के आधार पर एक भारतीय शिक्षा-दर्शन का निर्माण करें।

ऐसा करते समय हमें इन पाश्चात्य शैक्षिक विचारों को भी स्वीकार करने के लिये तैयार रहना चाहिए जो विद्यमान भारतीय शैक्षिक परिस्थितियों की दृष्टि से उपयोगी हों। किन्तु भारतीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परम्परा एक महासागर के समान है जिसका आवागमनकरना किसी एकल शोधकर्ता की सामर्थ्य से परे है। एकल शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिये या तो किसी काल-खण्ड का चयन कर सकता है। अथवा किसी विचारक के समस्त ग्रंथों को अथवा किसी एक ही ग्रंथ को। इसके अतिरिक्त यह तुलनात्मक दृष्टि से दो या अधिक काल खण्डों विचारों अथवा ग्रंथों को भी अपने अध्ययन के आधार पर बना सकता है। प्रस्तुत शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के लिये भारतीय ऋषि सत्ता के आधुनिक प्रतीक पुरुष- डा०सर्वेपल्लि राधाकृष्णन् को चुना है। समष्टि के मंगल के लिये ऋषि सत्ता सनातन काल से अपनी जीवन साधना द्वारा विचार-ज्योति की रचना करती रही है। भारत की विशिष्टता उन विदेशी चिन्तकों को जो मानव संस्कृति के अन्त स्पन्दन के पारखी के रूप में प्रख्यात रहे हैं, चमत्कृत करती रही है कि बड़े-बड़े अन्धड़ों से टकराकर भी भारत ने अपनी विचार-ज्योति को बुझने नहीं दिया है। अपनी मूल सम्पदा की बड़ी जागरूकता के साथ रक्षा की है। शताब्दियों तक भारत की नियति पर बैठी रहने वाली दासता ने इस देश को अनेक रूपों में क्षति

पहुँचाई हैं, किन्तु हर संकटकाल में भारत भूमि ऐसे ऋषियों—चिन्तकों को जन्म देती रही है, जो पाताल प्रविष्ट इसकी सांस्कृतिक जड़ों को अपनी साधना से पोषण देते रहे हैं, जिससे इसकी मूल पहचान को मटियामेट करने के सारे हीन प्रयास विफल होते रहे हैं सोलहवीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का काल भारत की पराधीनता का काल रहा है। इस काल में भी भारत की ऋषि—सत्ता अपनी विचार—ज्योति को चारों ओर फैलाती रही। 194 शताब्दी में भारत में स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, आदि महान विचारकों ने जन्म लिया। साथ ही दक्षिणी प्रदेश में इस शताब्दी में सर्वपल्लि राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। जो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे आलोक शिखरों का आखवभाव क्षेत्र रहा है। उसी समृद्धि दखिरणत्य आचार्य—परम्परा के आधुनिक प्रतिनिधि आचार्य राधाकृष्णन् थे।

डा० राधाकृष्णन् की साधना भारतीय परा विधा को आधुनिक चिन्तन—आयाम समृद्धि करने में अप्रतिम थी। पाश्चात्य तथा प्राच्य विद्यालोक को जोड़ने वाले विधायक विचार सेतु की रचना में भी उनकी विश्व प्रसिद्ध भूमिका रही है। इसी प्रख्यात विद्या साधक डा० राधाकृष्णन् को शोधकर्ता ने अपना शोध क्षेत्र चुना है। शोधकर्ता का विश्वास है कि स्वातयोत्तर भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों में डा० राधाकृष्णन के शैक्षिक मूल्यों में समन्वय करके योगदानों को प्रस्तुत कर सकता है। जो वर्तमान परिस्थितियों के

लिय सार्थक सिद्ध होंगे। इसी विश्वास में ही भारत के भविष्य की समस्त सम्भावनायें छिपी हैं।

Bibliography:–

1. **सिंह वी.पी. (1969)**“राजस्थान में अध्यापक शिक्षा के सेवारत कार्यक्रम में विभिन्नसंस्थाओं का योगदान”, उदयपुर राजस्थान।
2. **गुप्ता एस.पी. (1993)**“शिक्षा का ताना बाना”, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
3. **कुमार, प्रदीप (1990)**“वर्तमान शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अभ्यास–शिक्षण कार्यक्रम कितना व्यावहारिक–एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन”, एम.एड. डेजरटेशन, दयालबाग, आगरा।
4. **गुप्ता, विनीता (1995)**“ए कम्पैरेटिव स्टडी सेल्फ कान्सेप्ट एण्ड लेविल ऑफसरिप्रेशन ऑफ सेकेण्डरी स्कूल ट्रेनिंग विफोर एण्ड ऑफटर दी टीचिंग प्रैक्टिस”, एम.एड. लघु शोध, दयालबाग शिक्षा संस्थान, दयालबाग, आगरा।
5. **पौरुष कु० रेनुका (1996)**“शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक एवं संवेगात्मकपरिपक्वता पर शिक्षण–प्रशिक्षण अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन”, एम.एड. डेजरटेशनदयालबाग, आगरा।
6. **डॉ० मधु गुप्ता (1997)**“विभिन्न जाति वर्ग के शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिकउपलब्धि अभिप्रेरणा एवं अध्ययन संलग्नता का तुलनात्मक अध्ययन”, कु० रामचन्द्रमहिला महाविद्यालय मैनपुरी, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, अंक 16, राजस्थान।

7. जोशी एवं मेहता (1995) "शिक्षक प्रशिक्षण के सिद्धान्त और समस्यायें", राजस्थानहिन्दी अकादमी, जयपुर
8. शुक्ला, रमाशंकर (1989) "शिक्षक शिक्षा दशा और दिशा", अक्षय प्रकाशन, जयपुर
9. सक्सेना, एन.आर. मिश्रा वी.के. मोहन्ती आर.के. (2008), "अध्यापक शिक्षा", सूर्यापब्लिकेशन, मेरठ।
10. शिक्षा की चुनौती (1983) नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नईदिल्ली।